साप्ताहिक

# जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 30 दिसंबर 2024-5 जनवरी 2025 वर्ष-10, अंक-37 भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

## अटल सपना साकार-केन और बेतवा के जल का पीएम नरेंद्र मोदी ने किया संगम, कहा

### केन-बेतवा परियोजना से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में खुलेंगे समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार

# केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुझेगी बुंदेलखंड की प्यास

**-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा**

भोपाल/छतरपुर। जागत गांव हमार

पीएम नरेंद्र मोदी ने केन और बेतवा के जल का संगम कराया और दोनों नदियों को लिंक करने की परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण भी किया। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमिपूजन भी किया। मोदी ने कहा कि अतीत में कांग्रेस सरकारें, घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थीं। घोषणाएं करना, फीता काटना, दीया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देने से कांग्रेस का काम वहीं पूरा हो जाता था और उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पाता था। उन्होंने कहा कि शासन का मलतब भी यही है कि अपने ही हक के लिए नागरिकों को सरकार के सामने हाथ न फैलाना पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। यही तो शत प्रतिशत लाभार्थी को शत प्रतिशत लाभ से जोड़ने की हमारी नीति है। कांग्रेस पार्टी सत्ता के प्रति अपनी हकदारी का एहसास रखती है, वह राज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है, लेकिन जब शासन की बात आती है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड शर्मनाक है। वास्तव में, कांग्रेस शासन और सुशासन एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां सुशासन होता है, वहां न केवल वर्तमान चुनौतियों, बल्कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। हालांकि, दुर्भाग्य से हमारे देश पर लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा।

### हाथ जोड़कर राम-राम...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में बुंदेलखंडी बोली में किया, उन्होंने कहा- वीरों की धरती बुंदेलखंड में रहबे वाले, सबई जनन को हमारी तरफ से हाथ जोड़कर राम-राम पहुंचे। सीएम मोहन यादव की सरकार का एक साल पूरा हो गया है। इस एक साल में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। यहां आज हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शुरुआत हुई है। दशकों तक मध्य प्रदेश के किसानों, माताओं और बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया, क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थाई समाधान के लिए सोचा ही नहीं। जब देश में अटल जी की सरकार बनी, तब उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था, लेकिन 2004 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने अटल जी के सभी प्रयासों को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

### पीएम आधुनिक भारत के भागीरथ कांग्रेसी सिर्फ करते थे बड़े-बड़े वाद

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन भारत ही नहीं दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश की धरती पर आए। जैसी गंगा को धरती पर लाया गया था, वैसे ही नदी जोड़कर प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के भागीरथ बन गए हैं। मध्य प्रदेश में जब भी सूखे की खबर आती थी, तो बुंदेलखंड का नाम सबसे पहले जहन में आता था। लोग अपने घरों के गेट निकालकर उन्हें ईंटों के पैक करके रोजगार की तलाश में घर छोड़कर चले जाते थे। बड़ा कष्ट होता था कि हमारा ये क्षेत्र सालों तक सूखे का दंश झेलता रहा। कांग्रेस के लोग आते थे, सूखा दूर करने के लिए बड़े बड़े वादे करते थे। लेकिन कुछ नहीं किया, लेकिन नदी जोड़ो परियोजना से 10 जिलों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। चंबल नहर परियोजना से भी किसानों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में नवीन ऊर्जा के लिए ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर परियोजना का शुभारंभ हो गया है। सीएम ने कहा कि आज अटलजी की 100वीं जयंती है। उनकी जन्मस्थली ग्वालियर में आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में शासकीय पदों पर भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में 6 रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट की जा चुकी हैं। हमारी सरकार ने साल 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

- मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य जहां नदियों को जोड़ने के अभियान की हुई शुरुआत
- विकसित भारत के लिए विकसित मध्यप्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का होगा अहम रोल
- घोषणाएं करने, फीता काटने और तस्वीर छपवाने में माहिर थीं कांग्रेस सरकारें
- मध्य प्रदेश के 44 लाख और यूपी के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा
- केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपए
- 437 करोड़ की लागत से 1153 अटल ग्राम सदनों के निर्माण का भूमिपूजन
- अटल जयंती पर मोदी ने केन-बेतवा लिंक परियोजना की रखी आधारशिला
- परियोजना से एमपी और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को मिलेगा लाभ
- अब बुंदेलखंड में औद्योगीकरण और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
- हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर जनहित के कार्यों में सफलता पाई
- आजादी के बाद सबसे पहले नदी जल का महत्व आंबेडकर ने समझा
- पानी होगा तभी खेत-खलिहान होंगे। पानी होगा तभी उद्योग-धंधे होंगे
- कांग्रेस ने एक ही व्यक्ति को टिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया
- आजादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे, उन्हें साकार करने हम बहा रहे पसीना
- सीएम ने कहा-हमारी सरकार पांच साल में ढाई लाख लोगों को नौकरी देगी
- सीएम ने पीएम मोदी को भगवान राम के बाल काल की मूर्ति भेंट की

## सीएसआर फंड और राज्य बजट से वित्त पोषण, हर विकासखंड में एक वृंदावन ग्राम स्थापित होगा

# जिस गांव में दो हजार आबादी और पांच सौ गौवंश, वे बनेंगे 'वृंदावन'

भोपाल। जागत गांव हमार

ग्रामीणों को पशुपालन से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश के 313 विकासखंडों में एक-एक वृंदावन ग्राम बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार उन ग्रामों का चयन करेगी, जहां न्यूनतम जनसंख्या दो हजार और कम से कम पांच सौ गोवंश होंगे। इसका एक आधार पशुओं के लिए चारे, पानी के साथ परिवहन की अच्छी व्यवस्था भी रखा गया है। ग्राम का चयन प्रभारी मंत्री के परामर्श से कलेक्टर करेंगे। योजना के पर्यवेक्षण के लिए जिला अधिकारियों की समिति भी बनाई जाएगी। देश में दूध का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है।खेती रोजगार देने के साथ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है और इसे विस्तार देने के लिए सरकार ने कार्ययोजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुसार प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार ने प्रत्येक विकासखंड में एक वृंदावन ग्राम बनाने का निर्णय लिया है।

**गौवंश संरक्षण, संवर्धन**- इस ग्राम में गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए नस्ल सुधार के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, प्राकृतिक खेती के लिए जैविक खाद के उपयोग, उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ग्राम चिन्हित करने और पर्यवेक्षक के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।

### मार्केटिंग के साथ ब्रांडिंग पर रहेगा जोर

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वृंदावन ग्राम में गाय से प्राप्त उत्पाद की मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए स्व-सहायता समूह तैयार किए जाएंगे। इन्हें प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। स्थानीय, राष्ट्रीय मेल, किसान बाजारों और प्रदर्शनी में उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

### चारा उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा

चारा उत्पादन के लिए कृषि विभाग किसानों को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए फसल की जानकारी दी जाएगी। गोचर भूमि का संरक्षण और विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित कराया जाएगा।

### राज्य बजट के साथ सीएसआर का होगा उपयोग

वृंदावन ग्राम के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति राज्य के बजट के अलावा विभिन्न कंपनियों के सीएसआर फंड से कराई जाएगी। इसके लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग जिलों से प्राम विभिन्न कंपनियों के कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के प्रस्तावों पर समन्वय करेगा।

### सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हितेश कुमार मकवाना बोले

# मप्र ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग में अग्रणी राज्य, ड्रोन टेक्नोलॉजी गेम चेंजिंग : एससीएस

भोपाल। जागत गांव हमार

सीएम डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। राज्य में ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और ड्रोन नीति पर विचार विमर्श के लिए शासन में ड्रोन का उपयोग एवं मप्र में ड्रोन पारिस्थितिक तंत्र का विकास विषय पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यशाला हुई। कार्यशाला में ड्रोन प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोगों पर चर्चा की गयी। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हितेश कुमार मकवाना, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संजय दुबे, प्रबंध निदेशक एमपीएसईडीसी आशीष वशिष्ठ ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ड्रोन केन्द्र सूचना पोर्टल भी लांच किया गया। सर्वेयर जनरल मकवाना ने कहा कि भारत में पिछले छहवर्षों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। ड्रोन के शुरुआती सीमित उपयोग से लेकर आज इसके व्यापक उपयोग तक ड्रोन एक बहुउपयोगी उपकरण के रूप में उभरा है। भारत सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग के लिए ड्रोन नीति बनाई है। मध्यप्रदेश ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। राज्य ने स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन मे ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए विशेष उपलब्धि हासिल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी कुशल, सुलभ और कम लागत मे उपलब्ध टेक्नोलॉजी है।

## सेवाएं प्रदान करने में सक्षम

एसीएस संजय दुबे ने कहा कि केन्द्र ने ड्रोन नीति के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित इको-सिस्टम विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें ड्रोन के संचालन के लिए आवश्यक नियम, लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं, संचालन की अवधि आदि तय की गई हैं। मप्र इस नीति को प्रेरणादायक मानते हुए ड्रोन के क्षेत्रीय स्तर पर व्यवहारिक और लाभकारी उपयोग के लिए कार्य कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में एक मजबूत और समग्र इको-सिस्टम विकसित करें। जब हम ड्रोन की बात करते हैं तो यह केवल एक फ्लाइंग कैमरा ही नहीं बल्कि गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी विभिन्न स्तरों पर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। राज्य में इस टेक्नोलॉजी के व्यापक अनुप्रयोग की संभावनाएं है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा इको-सिस्टम विकसित करें, जिससे ड्रोन का व्यापक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से हो सके। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के आत्म-निर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। हमारा लक्ष्य ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित करने के साथ राज्य में निर्माण इकाइयों को स्थापित करना भी है।

### देश का ड्रोन हब बनाएंगे

एमपीएसईडीसी के एमडी आशीष वशिष्ठ ने कहा कि आज ड्रोन टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है। खनन क्षेत्र में ड्रोन के मदद से प्रभावी खनन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन की अहम भूमिका है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग आबकारी, कानून व्यवस्था, निर्माण गतिविधियों में भी किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य मध्यप्रदेश को देश का ड्रोन हब बनाना है।

### नमो ड्रोन दीदी

ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार विस्तार के लिए ड्रोन की परिवर्तनकारी भूमिका है। नमो ड्रोन दीदी जैसी पहल से ड्रोन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग केवल एक विकल्प नहीं बल्कि यह भविष्य की आवश्यकता है।

### प्रौद्यागिकी को नया आकार

नाबार्ड के जीएम कमर जावेद ने कहा कि मध्यप्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय कार्य हुए है। सहकारी संस्थाओं की तरह पैक्स सोसायटी में भी ड्रोन के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है। फिक्की ड्रोन कमेटी को-चैयरमेन एवं सीईओ अंकित मेहता ने कहा कि लॉ-एण्ड-ऑर्डर और निगरानी क्षेत्रों में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत उपयोगी है। ड्रोन अपनी बहुआयामी उपयोगिता के साथ नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। भविष्य की प्रौद्यागिकी को नया आकार दे रहे है।

### दिग्विजय सिंह ने सीएम को लिखा पत्र

# चाइनीज लहसुन से किसानों को भारी नुकसान

भोपाल। जागत गांव हमार

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चीन का प्रतिबंधित लहसुन मध्य प्रदेश की मंडियों में बेचे जाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि चीन का प्रतिबंधित लहसुन लगातार बाजार में आ रहा है। इससे लहसुन उत्पादक किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। चीनी लहसुन बाजार में आने का सुबूत यह है कि पिछले दिनों रतलाम में ऐसे दो ट्रक लहसुन को किसानों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दिग्विजय ने बताया कि मध्य प्रदेश के रतलाम, मदंसौर, नीमच सहित पूरे प्रदेश में अवैध तरीके से अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान के रास्ते से चीन का लहसुन आयात किया जा रहा है। इससे किसानों द्वारा उपजाए जाने वाले लहसुन की कीमत कम हो गई, जिससे 500 रुपए किलोग्राम की दर से लहसुन का बीज खरीदकर लगाने वाले किसानों को घाटा हो रहा है।

- नेपाल-बांग्लादेश के रास्ते हो रहा अवैध आयात
- सीमावर्ती देशों से लहसुन की जांच बढ़ाने की मांग
- रतलाम में किसानों ने चीनी लहसुन के ट्रक पकड़े
- किसानों को लहसुन की सही कीमत नहीं मिल रही

### देशभर में मंदसौर, नीमच की लहसुन की मांग

उल्लेखनीय है कि मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में किसानों द्वारा उत्पादित लहसुन की मांग पूरे देश में होती है। इंदौर सहित अन्य स्थानीय मंडियों के माध्यम से स्थानीय व्यापारी इस लहसुन को खरीदकर देश के अन्य भागों में विक्रय के लिए भेजते हैं।

### भारत आ रही चीनी लहसुन

कुछ दिन पूर्व मंदसौर जिले के नयाखेड़ा के पास दो लहसुन से भरी गाड़ियों को मंडी सचिव द्वारा अफगानिस्तान के कागज दिखाने के बाद भी बिना जांच पड़ताल के छोड़ दिया, जो अटारी बार्डर से बेंगलुरु की ओर जा रही थीं। मुख्यमंत्री से सीमावर्ती देशों के रास्ते भारत में बिकने आ रहे चीन के लहसुन की जांच करने केंद्र सरकार से अनुरोध करने की मांग की।

### केंद्र की पहलः प्राकृतिक खेती के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, केंद्र ने 2448 करोड़ की मंजूरी भी दी

# देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ाने में मदद करेंगे 7 शिक्षा संस्थान

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए देशव्यापी स्तर पर किसानों को प्रेरित और प्रशिक्षित करने के इरादे से 7 शिक्षा संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में चुना गया है। यह शिक्षा संस्थान किसानों को प्राकृतिक खेती करने के सही तरीके सिखाने के साथ ही उसके फायदे भी बताएंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने नेचुरल फार्मिंग मिशन के लिए 2448 करोड़ की मंजूरी भी दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से देश के 7 शिक्षा संस्थानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने समेत इसके लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी मिली है। इनमें

हिमाचल प्रदेश का डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विवि, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गुरुकुल शिक्षा संस्थान, कर्नाटक स्थित कृषि विज्ञान विवि धारवाड़, गुजरात प्राकृतिक खेती विज्ञान विवि, तमिलनाडु कृषि विवि, आंध्र प्रदेश की रायथु साधिकारा संस्था और झारखंड के रांची स्थित बिरसा कृषि विवि शामिल हैं। इन शिक्षा संस्थानों को नेचुरल फार्मिंग मिशन के लिए प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में चुना गया है।

**मिशन के लिए बनाएंगे 7 केंद्र** - विवि ने एग्रीकल्चर इकोसिस्टम पर यूरोपीय आयोग की ओर से वित्तपोषित एक्रोपिक्स प्रोजेक्ट के तहत 11 देशों के 15 से अधिक संस्थानों के साथ भागीदारी की है। इसके अलावा विवि ने एनसीईआरटी और कृषि स्नातकों के लिए प्राकृतिक खेती पाठ्यक्रम विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। नेचुरल फार्मिंग मिशन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए सभी 7 केंद्रों की पहली बैठक 22-23 दिसंबर को हैदराबाद में होगी।

### नेचुरल फार्मिंग को लेकर बढ़ेगी सक्रियता

डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विवि के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि इस मिशन के तहत एक केंद्र के रूप में चुना जाना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में हमारे विवि के अग्रणी प्रयासों को दर्शाता है। बीते कई वर्षों से हम प्राकृतिक खेती में अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में अग्रणी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह मान्यता प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक डेटा उत्पन्न करने की विवि की क्षमता को बढ़ाएगी और इस जलवायु अनुकूल, टिकाऊ कृषि दृष्टिकोण का समर्थन करेगी। हिमाचल प्रदेश में 1.7 लाख से अधिक किसान पहले से ही प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन किसानों से 40 रुपए प्रति किलोग्राम की अधिक दर से गेहूं और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की अधिक दर से मक्का। राज्य सरकार खरीद रही है। ऐसा करने वाला हिमाचल भारत का पहला राज्य है।

## सहकार से समृद्धि राज्य स्तरीय संगोष्ठी: मंत्री विश्वास सारंग ने कहा- देश को समृद्ध बनाना ही हमारा लक्ष्य

### -10 हजार नवगठित बहुउद्देश्यीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का उद्घाटन

# प्रदेश की हर पंचायत में पैक्स, सभी को रोजगार और सुव्यवस्थित सहकारी आंदोलन ही लक्ष्य

भोपाल। जागत गांव हमार

सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि हर पंचायत में पैक्स, सभी को रोजगार और सुव्यवस्थित सहकारी आंदोलन ही हमारा लक्ष्य है। सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए इसका विस्तार पंचायत स्तर पर करना होगा। सहकारिता के हर एक मूल भाव को आत्मसात करते हुए देश को समृद्ध बनाना ही हमारा लक्ष्य है। पैक्स के माध्यम से हर पंचायत तक रोजगार सृजित हो, इसके लिएबहुउद्देश्यीय पैक्स की अवधारणा गठित की गयी है। मंत्री भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। समारोह के पूर्व नई दिल्ली में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 हजार नवगठित बहुउद्देश्यीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम से सभी प्रदेशों के सहकारिता विभाग के अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। समृद्ध राष्ट्र के लिए समाज को जोड़ने की जरूरत है और समाज को जोड़ने का केवल एक ही प्रकल्प है, सहकारिता। समाज का निर्माण सहकारिता के माध्यम से ही होता है। सभी की भागीदारी के साथ लक्ष्य को साधने का नाम ही सहकारिता है। परिवार सहकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी सहकारिता के बिना कुछ नहीं हो सकता। सभी की भागीदारी अहम होती है।

### पैक्स के माध्यम से हों रोजगार सृजित

भागीदारी और बराबरी होने से अच्छे परिणाम निकलने का प्रतिशत बढ़ जाता है। सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिये सभी वर्ग को जुड़ना होगा। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हर पंचायत में पैक्स का लक्ष्य पूर्ण करने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। पैक्स के माध्यम से रोजगार सृजित हों और सदस्यों को लाभ मिले। पैक्स पशुपालन, मत्स्य-पालन और ऋण वितरण तक ही सीमित नहीं रहे, पैक्स पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी भी चलाए, जिसके पास जगह हो वह शादी हॉल, मैरिज गार्डन भी बनाएं, इससे पैक्स मजबूत होगा।

### सहकारी आंदोलन

अगले साल तक हर पंचायत में पैक्स हो, यही संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारा नारा है कि बिना सहकार नहीं उद्धार और बिना संस्कार नहीं सहकार। पूर्ण अनुशासन में संस्कार के साथ सहकारी आंदोलन को मध्यप्रदेश में स्थापित करने के लक्ष्य में सभी का सहयोग आवश्यक है।

### लक्ष्य निर्धारित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का भी लक्ष्य है कि रोजगार सृजित कर हर घर तक रोजगार पहुंचे। इसमें पैक्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। युवा साथियों के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि पैक्स बहुउद्देश्यीय हो जाए। जल्द ही हम सहकारी मंथन के माध्यम से नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के साथ संवाद करेंगे और अगले वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

### उत्कृष्ट अधिकारी तैयार करें

उत्कृष्ट काम करने वालों का हमेशा सम्मान होता है। इसलिए आज कार्यक्रम में भी उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया है। कनिष्ठों को उत्कृष्ट काम करने के लिए तैयार करें, जिससे वे वरिष्ठों की श्रेणी तक आने पर और ज्यादा सफल हो सकें।

### संभावनाएं अनंत

अपर मुख्य सचिव सहकारिता अशोक वर्णवाल ने कहा कि संभावनाएं अनंत हैं, तलाशने की जरूरत है। पैक्स को बिजनेस बढ़ाने और हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में काम करना होगा। इसके लिए सहकारिता संस्थाओं को आपस में भी व्यवसाय करने की जरूरत है।

### इन संस्थाओं का सम्मान

समारोह के दौरान सीबीएस पर काम करने वाली पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत हो चुकी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति नहारगढ़ (मंदसौर) के प्रबंधक पवन जैन, कम्प्यूटर ऑपरेटर सूरज विश्वकर्मा, मनासा (धार) के प्रबंधक राधेश्याम यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर सुनील यादव, सोनकच्छ (देवास) के प्रबंधक संतोष शुक्ला, कम्प्यूटर ऑपरेटर देवेन्द्र सिंह एवं अपेक्स बैंक द्वारा पूरे प्रदेश में 6 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक आयोजित विशेष ऋण महोत्सव में उत्कृष्ट कार्य करने हुए अधिकतम ऋण वितरित करने वाले शाखा प्रबंधकों क्रमश: श्री सुनील सिंघल, भरतपुर शाखा (उज्जैन), शैलेन्द्र रावत, फ्रीगंज (उज्जैन) एवं अशोक चंदेल, टीटी नगर (भोपाल) को भी पुरस्कृत किया। पूरे प्रदेश में अपेक्स बैंक ने निर्धारित लक्ष्य 50 करोड़ के विरुद्ध 50.13 करोड़ रुपए का ऋण इस अवधि में वितरित किया गया।

## खेती बनी लाभ का धंधा...लाखों का हो रहा मुनाफा

# सागर की सेम मचा रही देश के कोने-कोने में धूम

सागर। जागत गांव हमार

बुंदेलखंड अंचल के किसानों ने खेती में अलग प्रयास कर गजब कारनामा किया है। बुंदेलखंड के सागर जिले की मालथौन एवं बांदरी तहसील के किसानों ने पारंपरिक खेती से अलग सेम फली की खेती कर अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाया हैं। कुछ वर्ष पहले तक ये किसान सिर्फ पारंपरिक किसानी पर निर्भर थे। परंपरागत फसलों की बुआई करते थे। जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था, लेकिन अब अंचल के किसान न केवल आधुनिक पद्धतियों से किसानी कार्य कर रहे हैं, बल्कि नई नई फसलों की बुआई कर लाखों का मुनाफा भी कमा रहे हैं। बुंदेलखंड की सेम की फलियां अब आगरा, दिल्ली और देश के अन्य शहरों की सब्जी मंडियों की शोभा बढ़ा रही है। सागर जिले की बांदरी मालथौन तहसील क्षेत्र के किसान अब नकदी फसलों का उत्पादन लेने में रुचि दिखा रहे हैं और इन नकदी फसलों में से एक सेम की खेती है, जो इन किसानों को मुनाफे का सबब बन रही है।

### यह है लाभ का गणित

सेम की फसल उत्पादन करने वाले किसान बताते है कि एक एकड़ में अगर वह पारंपरिक फसल गेहूं की बोवनी करते हैं तो उन्हें 15 क्विंटल के करीब पैदावार ही मिल पाती थी, जो बाजार मूल्य अनुसार 32 हजार की होती है। जबकि इसी एक एकड़ रकबे में किसान प्रति सप्ताह 10 क्विंटल सेम का उत्पादन ले रहे है, जो बाजार मूल्य अनुसार 40 हजार की होती है और पूरे सीजन में किसान एक एकड़ में सेम की खेती से डेढ़ से 2 लाख कमा लेता है।

### सीधे खेत से हो जाती है बिक्री

किसान इसको लेकर किसी मंडी अथवा बाजार में बिक्री करने नहीं जाना पड़ता है, बल्कि सब्जी के थोक खरीददार इनके खेत से सीधे खरीदी कर ले जाते है। बांदरी के एक दर्जन से ग्रामों में सेम फली की खेती भारी मात्रा में की जा रही है, जहां से बुंदेलखंड की सेम फली को देश के दूर दराज बाजारों में भेजा जा रहा हैं। मुख्यत: इस सेम फली को आगरा, दिल्ली, पीलीभीत व ग्वालियर जैसे स्थानों पर व्यापारी बेचने ले जाते हैं।

### सेम की नकदी फसल

किसानों ने बताया कि चना, गेंहू, मसूर जैसी पारंपरिक फसलों में किसानों को उत्पादन लेने के लिए चार माह इंतजार करना होता है। इनमें तुषार पाला का खतरा ज्यादा होता है। इन फसलों में पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है। कुल मिलाकर इन फसलों में किसान को चार माह मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर उसको अनाज मिल पाता है। वहीं सेम की फसल नकदी फसल है, इसमें व्यापारी तुरंत भुगतान करते है। इस फसल का उत्पादन भी अच्छा होने से यह लाभ का धंधा है। इस कारण अंचल के अधिकांश किसानों का रुझान अब सब्जी वाली फसलों की तरफ बढ़ता जा रहा है।

## कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर बनाएं कार्य-योजना

# प्रदेश में मिलेट्स उत्पादन को किया जाए प्रोत्साहित

### मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की समीक्षा में दिए निर्देश

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारियों की समिति बनाकर कार्य-योजना विकसित की जाए। समिति में कृषक प्रतिनिधियों को भी अनिवार्यत: शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में रविवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। सीएम ने कहा कि मोटे अनाजों के उत्पादन से फसल लेने की लागत में कमी आएगी और कृषकों की आय में वृद्धि होगी। यह पहल किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार लाने और खेती को लाभ के व्यवसाय के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी।

### किसानों का करें सहयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तिलहन और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कृषकों को प्रेरित किया जाए। इसके लिए कृषकों को नवीन कृषि तकनीक, उन्नत बीज, उपयुक्त उर्वरक और कीटनाशक के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। बैठक में जानकारी दी गई की प्रदेश में धान का क्षेत्राच्छादन साधन 36 लाख 33 हजार हेक्टर क्षेत्र में है और उपार्जन के लिए 7 लाख 76 हजार किसान पंजीकृत हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

# सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने वर्ष 2024 में लिखा नया अध्याय

» पंकज मित्तल
प्र. संयुक्त संचालक, मप्र जनसंपर्क

प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों के फलस्वरुप वर्ष 2024 में मप्र में सिंचाई के क्षेत्र में नया अध्याय लिखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के नदी जोड़ो के सपने को साकार करते हुए प्रदेश में देश की दो बड़ी अति महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनों का आगाज हुआ। 17 दिसंबर को पीएम मोदी की उपस्थिति में जयपुर में पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना पर मप्र, राजस्थान और केन्द्र सरकार के बीच अनुबंध सहमति पत्र हस्ताक्षरित किए गए। पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को खजुराहो, छतरपुर में केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया।

केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, देश में भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे पहली और बड़ी सिंचाई परियोजना है।

मध्यप्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। इसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने अन्नदाता की रहती है। सरकार निरंतर हर खेत तक पानी पहुंचाने के कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट के नेतृत्व में प्रदेश के जल संसाधन विभाग की विभिन्न वृहद, मध्यम एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से मध्य-प्रदेश में निरंतर सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। किसान पहले दो फसल ले पाते थे, अब तीसरी फसल भी लेने लगे हैं। साथ ही कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। प्रदेश की धरती सुजलाम सुफलाम हो रही है।

सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश में सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्वज वृद्धि हुई है। वर्षज 2003 में जहां प्रदेश का सिंचाई रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश की निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में वर्ष 2025-26 तक सिंचाई का रकबा लगभग 65 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। सरकार ने वर्षज 2028-29 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य निधाज़रित किया है और उसके लिए प्रदेश में तेज गति से कायज़ किया जा रहा है। सरकार ने विभाग के लिए बजट में भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इस परियोजना से मध्यप्रदेश के 10 जिलों छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 44 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। फसलों के उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, ललितपुर एवं बांदा जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्यप्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना से मालवा और चंबल क्षेत्र की तस्वीर एवं तकदीर बदलेगी। सामाजिक और आर्थिज़क क्षेत्र में तरक्की होगी। इस परियोजना से प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र में 6 लाख 13 हजार 520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 60 वर्ष पुरानी चंबल दाई मुख्य नहर एवं वितरण तंत्र प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्य से भिंड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों के 1205 ग्रामों में 03 लाख 62 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों की मांग अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3217 ग्रामों को लाभ मिलेगा।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना मध्यप्रदेश एवं राजस्थान दोनों राज्यों के किसानों और नागरिकों के लिए वरदान साबित होगी। इससे किसानों को भरपूर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और विकास के नये द्वार खुलेंगे। परियोजना से दोनों राज्यों में समृद्धि आयेगी। परियोजना से मिलने वाले जल से किसान अपनी उपज को दोगुना कर सकेंगे, जिससे उनके परिवार के साथ प्रदेश भी समृद्ध होगा। पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 72 हजार करोड़ है, जिसमें मध्यप्रदेश 35 हजार करोड़ और राजस्थान 37 हजार करोड़ रूपये व्यय करेगा। केन्द्र की इस योजना में कुल लागत का 90 प्रतिशत केन्द्रांश और 10 प्रतिशत राज्यांश रहेगा। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। साथ ही 172 मिलियन घन मीटर जल, पेयजल और उद्योगों के लिये आरक्षित रहेगा। परियोजना अंतगज्त 21 बांध/बैराज निमिज्त किये जाएंगे। परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3217 ग्रामों को लाभ मिलेगा। परियोजना मध्यप्रदेश एवं राजस्थान दोनों राज्यों के किसानों और नागरिकों के लिए वरदान साबित होगी। इससे किसानों को भरपूर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और विकास के नये द्वार खुलेंगे। परियोजना से दोनों राज्यों में समृद्धि आयेगी। परियोजना से मिलने वाले जल से किसान अपनी उपज को दोगुना कर सकेंगे, जिससे उनके परिवार के साथ प्रदेश भी समृद्ध होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 72 हजार करोड़ है, जिसमें मध्यप्रदेश 35 हजार करोड़ और राजस्थान 37 हजार करोड़ रूपये व्यय करेगा। केन्द्र की इस योजना में कुल लागत का 90 प्रतिशत केन्द्रांश और 10 प्रतिशत राज्यांश रहेगा। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। साथ ही 172 मिलियन घन मीटर जल, पेयजल और उद्योगों के लिये आरक्षित रहेगा। परियोजना अंतर्गत 21 बांध/बैराज निर्मित किये जाएंगे। प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 बृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजना निर्माणाधीन हैं। प्रदेश में 1320 करोड रुपए की लागत वाली चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना से सिंगरौली जिले में 32125 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा। इसी प्रकार 4197 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत की जावद नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृत किया गया है। नीमच जिले में इस परियोजना से 18600 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा।

## कलौंजी (काला जीरा), एक महत्वपूर्ण औषधीय एवं मसाला फसल

» डॉ. वाय के शुक्ला
» डॉ. रश्मि शुक्ला
» डॉ. डी के वाणी
– कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा, मप्र।

कलौंजी, काला जीरा रनेनकुलेसी परिवार की बीजीय मसाला फसल है। इसका उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन क्षेत्र है और पश्चिमी एशिया से पूर्वी एशिया में इसका विस्तार हुआ। कलौंजी के उत्पादन में भारत, विश्व में प्रथम स्थान पर है। मप्र में रीवा, मंडला, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर जिलों में इसको बहुतायत से उगाया जाता है।

उत्तर भारत में इसकी बुआई रबी की फसल के रूप में की जाती है। प्रारंभ में वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडा मौसम अनुकूल होता है, जबकि बीज परिपक्व होते समय शुष्क एवं अपेक्षाकृत गर्म मौसम उपयुक्त होता है।

यद्यपि कलौंजी को विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, लेकिन पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ वाली बलुई दोमट मृदा उत्तम होती है। मृदा, भुरभुरी एवं उचित जल निकास वाली होनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई तथा दो-तीन उथली जुताइयों के बाद पाटा लगाना पर्याप्त होता है। बुआई से पूर्व खेत को सुविधानुसार छोटी-छोटी क्यारियों में बांट लेना चाहिए, ताकि सिंचाई के जल का फैलाव समान रूप से हो सके। इससे बीज का जमाव एक समान होता है और फसल अच्छी होती है। अगर मृदा में दीमक की समस्या है तो अंतिम जुताई के समय क्लिनॉलफॉस 1.5 प्रतिशत अथवा मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत में से किसी एक दवा की 25 किग्रा मात्रा को प्रति है. की दर से खेत में एक समान बिखेर कर मिला दें।

जब फसल 30.35 दिन की हो जाये, उसी समय कतारों से अतिरिक्त पौधों को भी निकाल देना चाहिए, ताकि फसल वृद्धि एवं विकास अच्छी तरह हो सके। दूसरी निराई-गुड़ाई 60.70 दिनों के बाद करनी चाहिए। इसके बाद अगर आवश्यक हो तो एक निराई और कर देनी चाहिए। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए पेन्डिमेथलिन दवा 1 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व को जमाव पूर्व 500.600 लीटर पानी में घोलकर मृदा पर छिड़काव करना चाहिए। इस विधि से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि में पर्याप्त नमी हो। उत्तर भारत में बुआई के लिए मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर सबसे अच्छा होता है।

**उन्नत किस्में: एन.आर.सी.एस.एस.एन.-1:** यह प्रजाति 135 दिनों में तैयार हो जाती है। यह जड़गलन रोग के प्रति सहनशील है। इसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विंटल/हैक्टर है। **आजाद कलौंजी:** यह 130-135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता 8.10 क्विंटल/ हैक्टर है। **एन.एस.-44:** यह 140 से 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता 4.5-6.5 क्विंटल/हैक्टर है। **एन.एस.-32:** यह 140 से 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता 4ण्5.5ण्5 क्विंटल/हैक्टर है। **अजमेर कलौंजी:** यह 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता 8 क्विंटल/हैक्टर है। **कालाजीरा:** यह फसल 135 से 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता 4.5 क्विंटल/ हैक्टर है। **अन्य किस्में:** राजेन्द्र श्याम एवं पंत कृष्णा।

**बीजदर:** सीधी बुआई के लिए 7 किग्रा बीज एक हैक्टर के लिए पर्याप्त होता है।

**बीजोपचार:** बीज को बुआई से पूर्व कैप्टॉन, थीरम व बाविस्टीन से 2.5 ग्राम प्रति कि.ग्रा. की दर से उपचारित करना चाहिए।

**बुआई की विधि:** कतार विधि: इस विधि में बीज की बुआई 30 सें.मी. की दूरी पर बनी कतारों में करनी चाहिए। बीज बोते समय यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गहराई 2 सें.मी. से ज्यादा न हो अन्यथा बीज जमाव पर इसका असर पड़ता है।

**सिंचाई।** पुष्पण एवं बीज विकास के समय मृदा में उचित नमी का होना आवश्यक है। अच्छी पैदावार के लिए कुल 5 . 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है।

**फसल संरक्षण: जड़ सड़न:** यह रोग राइजोक्टोनिया और फ्रयूजेरियम द्वारा संयुक्त रूप से उत्पन्न होता है। इस रोग में रोगग्रस्त पौधे पहले तो पीले दिखते हैं तथा बाद में पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा मर जाता है। इससे बचाव के लिए बीज को बुआई से पूर्व ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति कि.ग्रा.बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। गर्मी की जुताई एवं उचित फसलचक्र अपनाने से जड़ रोग का प्रकोप कम होता है।

**सड़न की रोकथाम: माहू, एफिड:** इस कीट के वयस्क तथा प्रौढ़ फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये फसल के कोमल हिस्सों से रस चूसते हैं। इस कारण फसल की उपज घट जाती है। इसके नियंत्रण के लिए 0.1 प्रतिशत मैलाथियान 50 ईसी अथवा 0.03 प्रतिशत डाइमेथोएट 30 ई.सी. दवा के 500 लीटर घोल का प्रति हैक्टर की दर से प्रभावित फसल पर छिड़काव करना चाहिए।

**दीमक:** यह कीट कलौंजी को काफी क्षति पहुंचाता है। दीमक फसल के विभिन्न भागों को खाकर हानि पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए 4 लीटर प्रति हैक्टर की दर से क्लोरोपाइरीफॉस को पानी में मिलाकर सिंचाई के साथ दें।

**खाद व उर्वरक:** भूमि की तैयारी के समय अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कम्पोस्ट 10 क्विंटल प्रति हैक्टर की दर से खेत में मिला देनी चाहिए। सामान्य उर्वर क्षमता वाली भूमि में 40 कि.ग्रा.नाइट्रोजन, 20 कि.ग्रा. फॉस्फोरस तथा 20 कि.ग्रा. पोटाश का प्रति हैक्टर प्रयोग करना चाहिए। एक तिहाई नाइट्रोजन तथा सम्पूर्ण फॉस्फोरस मृदा में अंतिम जुताई के समय मिला देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को दो भागों में बांटकर बुआई के 30 और 60 दिनों बाद खड़ी फसल में सिंचाई के साथ देना चाहिए।

**फसल कटाई:** प्राय: कलौंजी की फसल 140 . 160 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पौधे को हंसिए से काट लेते हैं। इसके बाद छोटे-छोटे बंडल बनाकर अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। बीज को डंडे से पीटकर या रगड़कर अलग करते हैं। इसके बाद बीजों को सुखाकर बोरियों में भरकर रखते हैं। **उपज:** औसतन 8.10 क्विंटल बीज/ हैक्टर प्राप्त किया जा सकता है।

## रानी मेवा (मौलश्री): औषधीय गुण

» रोमा वर्मा
शोध छात्रा, शाक सब्जी विभाग महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन (दुर्ग) छत्तीसगढ़।

मौलश्री को रानी मेवा भी कहते हैं। यह मरुभूमि मृदा में पानी की कमी के होते हुए भी त्वरित रुप से बढ़ने वाला एवं जन, पशु एवं वन्य जीदों के लिए भोजन प्रदान करने वाला फल वृक्ष है। इस वृक्ष का वानस्पतिक नाम मैनिलकारा हैक्सैण्ड्रा है।

इस वृक्ष को हमारे देश में विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है-जैसे हिन्दी खिरनी, बंगला-खिरखेजुर, मराठी रंजना, रयान, रैनीच गुजराती-रयान, खिरनी, तेलगू-मंजीपाला, पाला, तमिल-पाल्ला, पालाई, कन्नड़-वाकुला, मलियालम पाला,उड़िया-खीरी खीराकली, राजस्थान-रानी- मेवा, खिरनी तथा मौलश्री एवं बकुल भी कहते हैं। अंग्रेज लोग इसे स्पेनिश चेरी के नाम से पुकारते हैं रामचरित मानस में वर्णित है कि चित्रकूट में भगवान राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी अपनी कुटी के आस-पास बकुल, आम तथा केला लगाये थे।

मौलश्री मध्य भारत एवं दक्षिण प्रायद्वीप में पाया जाने वाला मध्यम आकार का, सदा हरित, वृक्ष है, जिसका शिखर विस्तृत तथा प्रस्तम्भ सीधा स्थूल होता है। भारत के अधिकांश भागों में (शुष्क इलाके को छोड़कर) केवल बाग-बगीचों में ही एक या दो वृक्ष छाया प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाये जाते है। इस वृक्ष की पत्तियाँ दीर्घ वृतीय-प्रति अंडाकार अथवा दीर्घायत, चर्मिल, व फूल ज्यादातर गुच्छों व अकेले भी लगते हैं। इनका रंग हल्का हरा या पीले रंग का होता है। फल नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में लगते हैं जो मई के अन्त तक पकने लगते हैं। फलों में कार्बोज, प्रोटीन, वसा कैल्सियम विटामिन सी ,तथा फास्फोरस, लोहा तथा पोटाश होती है। मौलश्री के फल रूचिकर, मूत्रल, ज्वरहर, उद्देष्टहर, तथा किटाणुनाशक होते हैं।

मौलश्री के सूखे फूलों का चूर्ण शिर:शूल, कास, कृमिरोग में काफी प्रभावशाली होता है। वृक्षों की छाल का क्राथ पुराने ज्वर को समाप्त कर देता है। पुरानी पेचिश होने पर पके फलों का सेवन लाभप्रद होता है। दन्त विकारों में मौलश्री की दातून करना लाभकारी होता है तथा इसके बाद कच्चे 4-5 फलों को चबा कर खाना चाहिए। मौलश्री के छाल का क्राथ पीने तथा ताजे फूलों का हार पहनने से हृदय रोग में लाभ होता है। मौलश्री के 20 ताजे फूलों को तीन बादाम, तथा तीन ग्राम चीनी के साथ पीस कर पिलाने से 21 दिनों में किसी भी प्रकार का प्रदर रोग समाप्त हो जाता है। मौलश्री का सेवन विसूचिका रोग में, अर्श में, तथा मुख रोग में फायदेमन्द साबित हुआ है।

-किसानों की चिंता दूर...अब कपास की गुलाबी सुंडी का होगा सफाया

## -गुलाबी सुंडी गुजरात में 2015 में और महाराष्ट्र में 2017 में पहली बार रिपोर्ट की गई। कपास की पैदावार को कम कर दिया

# आईसीएआर-सीआईसीआर ने बनाया एआई से चलने वाला फेरोमोन ट्रैप

भोपाल। जागत गांव हमार

आईसीएआर ने पंजाब में कपास की फसल के लिए एआई आधारित एक फेरोमोन ट्रैप बनाया है जो गुलाबी सुंडी के प्रकोप से फसल को बचाने में मदद करेगा। पंजाब में कपास की फसल के लिए गुलाबी सुंडी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है क्योंकि बीटी कपास पर इसकी दवा का कोई असर नहीं होता। पंजाब ही नहीं बल्कि देश के सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में गुलाबी सुंडी ने आतंक मचा रखा है। सीआईसीआर का एआई पर चलने वाला फेरोमोन ट्रैप रियलटाइम में किसानों को गुलाबी सुंडी के अटैक के बारे में जानकारी देगी जिससे फसल बचाव में मदद मिलेगी। गुलाबी सुंडी गुजरात में 2015 में और महाराष्ट्र में 2017 में पहली बार रिपोर्ट की गई। इसकी बड़ी तादाद 2018-19 तक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैल गई। जलावन के लिए कपास के डंठलों को जुटाकर रखने से इस कीट का संक्रमण और बढ़ गया, जिससे पंजाब (2022) और राजस्थान (2023) में प्रकोप हुआ। सुंडी ने कपास की पैदावार को कम कर दिया और फाइबर की क्वालिटी को प्रभावित किया। इससे किसानों को धान, तिलहन और दालों जैसी अधिक लाभ देने वाली फसलों की ओर रुख करना पड़ा। नतीजतन, पंजाब में कपास का रकबा 2018 में 2.68 लाख हेक्टेयर से घटकर 2024 में 0.97 लाख हेक्टेयर रह गया, जबकि उत्पादन 2018 में 12.2 लाख गांठ से घटकर 2023 में 4.73 लाख गांठ रह गया।

### रहस्यमयी गुलाबी सुंडी

गुलाबी सुंडी के साथ कई ऐसी बातें हैं जिससे उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक तो फसलों पर इसका बर्ताव बहुत रहस्यमय होता है। यह सुंडी कब दिखेगी, कब नहीं इसे लेकर किसान अक्सर अचंभे में रहते हैं। दूसरी बात ये कि इसका जीवन च बहुत छिपा रहता है। कब किस स्टेज में पहुंच जाए उसकी जानकारी जल्दी नहीं मिल पाती। यही वजह है कि इसकी मॉनिटरिंग और इसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इसके लिए फेरोमोन ट्रैप पहले भी बनाए गए हैं, लेकिन उतने कारगर नहीं हैं। जैसे सेक्स फेरोमोन ट्रैप केवल वयस्क कीटों को ही पकड़ पाता है और इसी आधार पर कीटनाशक छिड़काव का फैसला लिया जाता है। इसी आधार पर कीटनाशकों को बनाया भी जाता है। लेकिन यह काम मुश्किल होता है।

### पंजाब में चला खास प्रोजेक्ट

पंजाब में कपास के किसानों को एआई ट्रैप प्रोजेक्ट से बहुत लाभ हुआ है, उन्हें समय पर कीट अलर्ट और कीट प्रबंधन सलाह उनके मोबाइल फोन पर मिल रही है। मानसा जिले के खियाली चाहियांवाली गांव के जगदेव सिंह ने कीट निगरानी और ईटीएल-आधारित कीटनाशक के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट की तारीफ की। साप्ताहिक अलर्ट और फील्ड विजिट ने उन्हें सही समय पर कीटनाशकों का इस्तेमाल करने में मदद की, जिससे उनकी फसल सुरक्षित रही। इसी तरह, श्री मुक्तसर साहिब के रामगढ़ चुंगा गांव के जगसीर सिंह ने इस पहल के लिए कृषि मंत्रालय के प्रति आभार जताया, जिसने न केवल कीट मुक्त कपास की उपज सुनिश्चित की बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि की।

### इस टीम ने बनाया ट्रैप

पारंपरिक फेरोमोन ट्रैप की सीमाओं को दूर करने के लिए, डॉ.वाईजी प्रसाद और डॉ. के रामेश के नेतृत्व में आईसीएआर-सीआईसीआर ने पिंक बॉलवर्म (गुलाबी सुंडी) की रियलटाइम में निगरानी के लिए एआई-आधारित स्मार्ट फेरोमोन ट्रैप बनाया। यह स्मार्ट ट्रैप हर घंटे लाइव डेटा भेजता है - जिसमें तस्वीरों, कीटों की संख्या और मौसम की जानकारी शामिल है। इसका डेटा सीधे क्लाउड और रजिस्टर्ड यूजर्स जैसे किसान और इससे जुड़े अधिकारियों को मिलता है। एआई आधारित यह फेरोमोन ट्रैप गुलाबी सुंडी का पता लगाने और उनकी गिनती करने में 96.2 परसेंट तक सटीक है। इसका डेटा पाने के लिए एक एंड्रॉइड और डेस्कटॉप ऐप बनाया गया है जिससे किसानों को गुलाबी सुंडी के बारे में जानकारी मिलती है और उसी आधार पर एक्शन लिया जाता है। पंजाब के तीन प्रमुख कपास उत्पादक जिलों के 18 गांवों में स्मार्ट ट्रैप लगाए गए, जिनमें प्रत्येक जिले में छह यूनिट लगाई गई।

-89 नदियों की जांच में 60 धार्मिक स्थलों के पास पानी बेहद प्रदूषित

# सावधान! मप्र की नदियां हो रहीं 'मैली'

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट ने राज्य की नदियों की चिंताजनक स्थिति उजागर की है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश की 89 नदियों में से 60 धार्मिक स्थलों के पास का पानी इतना प्रदूषित है कि आचमन, स्नान या हाथ धोने तक के लायक नहीं है। राज्यभर में 293 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की जांच की गई, जिसमें से केवल 197 स्थानों का पानी ए-कैटेगरी (पीने योग्य) पाया गया, जबकि 96 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता खराब थी। धार्मिक स्थलों के पास नदियों की स्थिति इतनी खराब है कि क्षिप्रा, नर्मदा और बेतवा जैसी पवित्र नदियों के धार्मिक स्थलों के पास का पानी स्नान या पीने योग्य नहीं है। वहीं इंदौर की कान्ह नदी को राज्य की सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया गया है। देवास की छोटी कालीसिंध नदी की तो वह पूरी तरह सूख गई है, जिस कारण उसकी जांच भी नहीं हो सकी।

### नदियों की गुणवत्ता: पांच श्रेणियों में वर्गीकरण

- ए-कैटेगरी: रोगाणु मुक्त और सीधे पीने योग्य।
- बी-कैटेगरी: बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव मौजूद; केवल धुलाई और सफाई के लिए उपयुक्त।
- सी-कैटेगरी: भारी धातु और अन्य प्रदूषकों से प्रभावित।
- डी-कैटेगरी:काला पानी; अत्यधिक प्रदूषित।
- ई-कैटेगरी:औद्योगिक अपशिष्ट और जहरीले प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित।

### प्रमुख नदियों की स्थिति

- कान्ह नदी (इंदौर): रामवासा क्षेत्र में पानी डी-कैटेगरी का पाया गया। खाटीपुरा और धानखेड़ी जैसे क्षेत्रों में ई-कैटेगरी का अत्यधिक प्रदूषित पानी मिला।
- क्षिप्रा नदी (उज्जैन): रामघाट और सिद्धवट घाट से महिदपुर तक पानी काला और डी-कैटेगरी का है।
- नर्मदा नदी (अमरकंटक): उद्गम स्थल पर पानी बी-कैटेगरी का है। बुदनी क्षेत्र में स्थिति खराब है।
- चंबल नदी (राजगढ़): पानी डी-कैटेगरी का पाया गया।
- बेतवा नदी (मंडीदीप): चरणतीर्थ और भोजपुर मंदिर के पास पानी बी-कैटेगरी का है।

### योजना फाइलों में अटकी

नदियों की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए 32 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना तीन साल से ठप है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 110 नगरीय निकायों को अपशिष्ट जल का उपचार और नदियों में गंदा पानी जाने से रोकने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब तक केवल 2-10 प्रतिशत काम पूरा हो सका है।

### परियोजनाओं की स्थिति

**नर्मदा नदी:** बुधनी में काम पूरा हुआ, लेकिन शाहगंज में काम शुरू भी नहीं हुआ।

**सुनार नदी ( सागर ):** 97 लाख मंजूर होने के बावजूद सफाई और पौधरोपण का काम अधूरा।

**बागेड़ी नदी ( धार ):** 67 लाख रुपए स्वीकृत, लेकिन गाद निकालने का काम लंबित।

### प्रदेश की छोटी नदियों की स्थिति दयनीय

सरकार ने नदियों के संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही है। लेकिन मिशन क्लीन गंगा जैसे अभियानों में शामिल होने के बावजूद राज्य की छोटी और धार्मिक नदियों की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

-आए अच्छे दिन...कुछ महीनों में हो गई बढ़िया कमाई

# नमो ड्रोन दीदी योजना से आत्मनिर्भर बनी निधा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर आगे भी बढ़ रही है। इसी क्रम में हम आपको एक ड्रोन दीदी की कहानी बताने जा रहे हैं, जो मप्र में चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल, ग्वालियर के मोहना और इसके आस-पास के गांवों में इन दिनों ड्रोन दीदी निधा की चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने चंद महीनों में साढ़े तीन लाख रुपए आय हासिल की है। निधा ड्रोन तकनीक से नैनो खाद का छिड़काव का काम करती हैं। वे इलाके में कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति को आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही इस काम के जरिए आत्मनिर्भर बनकर महिला सशक्तिकरण की इबारत लिख रही हैं। सरकार की ओर से चलाई जा रही नमो ड्रोन दीदी योजना से निधा का जीवन बदल गया है। ग्वालियर जिले की नगर परिषद मोहना की रहने वाली निधा अख्तर कहती हैं कि भारत सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी है। उन्होंने मोहना और आसपास के गांवों के 325 किसानों के खेतों में धान, मटर, सरसों, टमाटर और अन्य सब्जियों की फसलों के लगभग 2250 एकड़ रकबे पर ड्रोन से नैनो खाद का छिड़काव किया है। निधा का कहना है कि नैनो खाद छिड़काव से एक साल से भी कम समय में उन्हें लगभग साढ़े तीन लाख रुपये की आय हुई है।

### इफको ने ट्रेनिंग और किट दिलाई

निधा ने बताया कि उन्हें नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत इफको की ओर से ग्वालियर के एमआईटीएस कॉलेज में ड्रोन उड़ाने की फ्री ट्रेनिंग दिलाई गई। इसके बाद उन्हें संचालनालय नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार से ड्रोन पायलट का लायसेंस मिल गया। लायसेंस मिलने पर इफको ने एक ड्रोन, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी और एक जनरेटर उपलब्ध कराया। निधा कहती हैं कि अब वह अपनी आर्थिकी के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं।

### मौके और मार्गदर्शन की जरूरत

निधा अपने आत्मविश्वास, मेहनत और तकनीकी समझ से सफलता हासिल कर इलाके की महिलाओं के लिये प्रेरणास्त्रोत बन गई हैं। निधा और उनकी जैसी तमाम महिलाओं की कहानी वे बयां करती है कि उन्हें सिर्फ एक अवसर और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। भारत सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना से हजारों महिलाओं को स्व-रोजगार हासिल हुआ है। इससे न सिर्फ उनकी कमाई हो रही है, बल्कि उनके पूरे परिवार का जीवनस्तर सुधर रहा है।

### नैनो खाद को मिल रहा बढ़ावा

सरकार रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करने के लिए नैनो खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। किसान इसके इस्तेमाल की सही जानकारी न होने पर बचते नजर आते हैं। लेकिन, अब ड्रोन दीदियों के माध्यम से नैनो खाद का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जिससे ड्रोन दीदी की भी आय हो रही है और किसानों की लागत व समय की बचत हो रही है।

### कृषि विज्ञान केंद्र में मत्स्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

# मछली से निर्मित मूल्यवर्धित उत्पादों से आजीविका एवं स्वरोजगार की संभावनाएं

## आय बढ़ाने मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया

**टीकमगढ़। जागत गांव हमार**

मूल्य संवर्धन वर्तमान समय में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मछली प्रसंस्करण उद्योग के द्वारा जहां काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वही दूसरी ओर मछली से निर्मित मूल्यवर्धित उत्पाद के द्वारा आजीविका एवं स्वरोजगार की काफी संभावनाएं हैं। मछलियों से निर्मित उत्पाद की लोकप्रियता द्वारा मछली पालकों की आय बढ़ाई जा सकती है साथ ही साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुपोषण जनित बीमारियो एवम समस्याओं पर लगाम लगाइ जा सकती है। इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए, कृषि विज्ञान केन्द्र, टीकमगढ़ एवं रायकवार (माझी) आदिवासी परिषद, टीकमगढ़ के संयुक्त प्रयास से रोजगार एव आजीविका स्थापित करने के लिए मत्स्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर कौशल विकास कार्यशाला कार्यशाला, दिनांक 20 दिसम्बर 2024 से 22 दिसम्बर 2024 तक कृषि विज्ञान केन्द्र, टीकमगढ़ मे आयोजित की गई। कृषि विज्ञान केंद्र, डिंडोरी द्वारा तीन दिवसीय मत्स्य प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन विषय पर दिनांक 26 से 28 मई 2022 के दौरान उधमिता विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवम प्रमुख डॉ. वीरेन्द्र सिंह किरार एव रायकवार (माझी) आदिवासी परिषद, टीकमगढ़ के सकिय सदस्य गोपाल दास कडा के जिले मे मछली से बने रेडी टू ईट उत्पाद की सम्भावना और उसके द्वारा सम्भावित स्थानीय मछली पालको के लिये आजीविका एवं स्वरोजगार की सोच पर कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के मत्स्य विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. सतेन्द्र कुमार, वैज्ञानिक (मात्स्यिकी) के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया । कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ द्वारा रायकवार (माझी) आदिवासी परिषद, टीकमगढ़ के विशेष अनुरोध एवं सहायता पर किया गया था।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र मे कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवम प्रमुख डॉ. वीरेन्द्र सिंह किरार ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुये और अपने उद्घाटन उद्बोधन में मत्स्य प्रसंस्करण और मछ्ली से निर्मित मूल्यवर्धित उत्पाद की टीकमगढ़ जिले मे मांग व सम्भावना पर चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक डॉ. सतेन्द्र कुमार, वैज्ञानिक (मात्स्यिकी) ने बताया कि मछ्ली से निर्मित मूल्यवर्धित उत्पाद कुटीर उद्योग के रूप में ग्रामीण आजीविका एवं पोषण सुरक्षा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। उन्होने प्रशिक्षणार्थियों को मछ्ली से निर्मित विभिन्न उत्पाद जैसे फिश कट्लेट, मछली का अचार, मत्स्य पापड़, मत्स्य पापडी, मत्स्य चकली, मत्स्य कटलेट, शाकाहारी- हर्बल की चटनी और मत्स्य सेव बनाने की विधियां की जानकारी दी और प्रशिक्षणार्थियों ने समूह बनाकर उपरोक्त उत्पाद बनवाये । कार्यक्रम में आए किसानों और महिलाओं को कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉ. डी एस तोमर अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ द्वारा मत्स्य उपोत्पादों के लागत प्रभावी उत्पादन और अंततः उनकी आय बढ़ाने के लिए स्वयं मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

### टीकमगढ़ साथ ही छतरपुर एवं निवाड़ी जिले के किसानों ने भी भाग लिया

इस कार्य म में टीकमगढ़ जिले के अलावा छतरपुर एवं निवाड़ी जिले के किसानों ने भी भाग लिया। टीकमगढ़ जिले के सभी तहसीलों से प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति देखि गई और खास रूप से मंडुमर, नन्हीटेहरी, फिरोजपुरा, नरगुडा आदि ग्रामों से मछली पालक कृषक एवं महिला कृषक बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यशाला में काफी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवतियां ने भाग लिया और मत्स्य प्रसंस्करण एवं मछली से बनने वाले अन्य उत्पाद के बारे में अपनी जिज्ञासा को शांत किया। कार्यशाला स्थल कृषि विज्ञान केंद्र मे पहुँचकर कुल 56 व्यक्ति यो ने पंजीयन कराकर प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमे 95 संख्या महिलाये एव युवतियो की थी। कार्यशाला में एमएससी, एम ए, बीएससी एवं बीए डिग्री धारी युवतियों ने भी भाग लिया और मछली से मूल्य संवर्धन एवं मूल्य वर्धित उत्पाद बनाना सिखा। यूवतियों ने अपने द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को डॉ. सतेन्द्र कुमार के मार्गदर्शन में कार्य म में आए अतिथियों के सामने प्लेटो में सजाकर विभिन्न तरीकों से में प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत किया । प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विभिन्न उत्पाद जैसे मछली का अचार कटलेट हर्बल चटनी आदि के इस तरह के व्यवसायिक प्रदर्शन को देखकर कार्य म में पधारे अतिथि काफी प्रभावित हुए।

### कार्यशाला मे जिज्ञासा का विषय बना रहा मछली का अचार

इस कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र की द्वारा तैयार कराये जा रहे मछली का अचार एवं मूल्य वर्धित उत्पाद की आम लोगो के बीच काफी चर्चा रही। मछली का आचार अधिकतर लोगों के लिए कौस्तुक का विषय बना हुआ था । सबसे बड़ी बात यह थी कि यह अचार भाखा जिले के स्थानीय स्व सहायता समूह / समिति की महिलाओ द्वारा तैयार कराया जा रहा था। लोगों में जिज्ञासा थी की मछली का अचार भी होता है? इसके क्या फायदे हैं ? यह कैसे बनाया जाता है ? यह कितने दिनों तक खराब नही होता ? क्य यह सभी मछलियो मछलियो से बनाये जा सकते है ? यह टीकमगढ़ की मछलियों से भी बनाए जा सकते हैं क्या ? आदि ! कार्यशाला के समापन सत्र में आए नावार्ड बैंक के जिला विकास अधिकारी (डीडीएम), टीकमगढ़ मिर्ज़ा फैसल बेग ने कार्यक्रम की काफी सराहना की और कहा कि ऐसे कार्य म वृहत स्तर पर करने की जरुरत है ताकि मूल्यवर्धित मत्स्य उत्पाद के प्रति लोगों की जागरूकता और लोकप्रियता बढ़ाई जा सके । कमलेश रैकवार जनप्रतिनिधि डमडमा, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी ने कृषि विज्ञान केंद्र से अनुरोध किया कि निवाडी जिले के किसानो के लिये भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाये । ए.के. शर्मा, उपसंचालक, कृषि विभाग, टीकमगढ़, पीके बाजपेई, वित्तीय साक्षरता सलाहकार, जिला अग्रणी बैंक, टीकमगढ़, पुर्व सहायक संचालक मत्स्योद्योग, आर के मिश्रा, ओम प्रकाश रैकवार व मूलचंद कड़ा (मशः अध्यक्ष व सचिव, रायकवार (माझी) आदिवासी परिषद, टीकमगढ़), और गोप ने प्रशिक्षणार्थियों मार्गदर्शन प्रदान किया । उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार की गई मछली का पापड, चकली, पापडी, सेव, अचार और अन्य सामग्रियों का अवलोकन किया तथा जानकारी ली । इस कार्य म के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के वैज्ञानिक डॉ. आर.के. प्रजापति, डॉ. एस.के. सिंह, डॉ. यू.एस. धाकड़, डॉ. एस.के. जाटव व जयपाल छिगारहा और रायकवार (माझी) आदिवासी परिषद, टीकमगढ़ के गोपाल दास कडा, अवध किशोर रैकवार भोला राम रैकवार का योगदान सराहनीय रहा।

# कृषक एवं वैज्ञानिक कृषिवानिकी राजदूत अवार्ड से हुए सम्मानित किए गए किसान

**शिवपुरी। जागत गांव हमार**

भाकृअनुप-केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा कृषिवानिकी को बढ़ावा देने और कृषिवानिकी तकनीकियों को अपनाते हुए प्रसारित करने के लिए कृषिवानिकी राजदूत (एग्रोफोरेस्ट्री एम्बेसडर) घोषित करते हुए राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर 10 कृषकों एवं कृषि वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिवपुरी जिले के कृषक रामगोपाल गुप्ता ग्राम भौंती विकासखण्ड पिछोर को आंवला आधारित कृषिवानिकी को बढ़ावा देने एवं अपनाने के लिए तथा कृषक महिम शर्मा ग्राम बड़ागांव विकासखण्ड शिवपुरी को आम आधारित कृषिवानिकी को अपनाने तथा प्रसारित करने के लिए, रवि गोयल निदेशक शक्तिशाली महिला संगठन समिति शिवपुरी को महिलाओं को पोषण वाटिका, स्वास्थ्य के साथ-साथ उपयोगी पौधों के महत्व उपयोगिता तथा पौधारोपण को बढ़ाते हुए जनजातीय बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिवानिकी, बाउण्ड्री प्लांटेशन जैसी विधाओं को बढ़ावा देने के लिए और डॉ. मुकेश कुमार भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी को कृषिवानिकी संस्थान की उपयोगी तकनीकियों को संस्थान के निदेशक डॉ. ए. अरूणाचलम एवं एटिक के प्रभारी डॉ. आर. पी. द्विवेदी, प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार से समन्वय करते हुए कृषिवानिकी पद्धतियों एवं मॉडलों के क्षेत्र के अनुकूल एवं उपयोगी बनाते हुए शिवपुरी जिले में कृषिवानिकी को भी बढ़ावा देने के लिए कृषिवानिकी राजदूत घोषित किया गया। शिवपुरी जिले में कृषिवानिकी के प्रमुख उदाहरणों में हल्की लाल कंकरीली भूमि में आंवला, बेर फल वृक्षों के साथ उचित फसलों जिसमें मूंगफली-उर्द का फसल चक्र एवं अमरूद, आम जैसे फल वृक्षों के साथ कृषिवानिकी अंतर्गत सोयाबीन-गेहूं फसल चक्र का संयोजन और ब्लॉक प्लांटेशन में बांस और सहजन रोपण के साथ-साथ नवीन मूल्यवान फसलों में ड्रैगनफ्रूट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यह आयोजन केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में मुख्य अतिथि रविन्द्र शुक्ला पूर्व कृषि मंत्री उप्र सरकार एवं विशिष्ट अतिथि धर्मेन्द्र कुमार उपसंचालक मृदा संरक्षण झांसी एवं संस्थान के निदेशक डॉ. ए अरूणाचलम एटिक प्रभारी डॉ. आरपी द्विवेदी, प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एके हाण्डा की सहभागिता रही।

### मार्च तक होगी बेहतर आमदनी

# जनवरी के महीने में शुरू करें इन सब्जियों की खेती

**भोपाल। जागत गांव हमार**

नए साल की शुरुआत के साथ ही किसान कई नई फसलों को भी खेतों में लगाते हैं, जिनमें से कई फसलें तो ऐसी होती है जो किसानों को होली से पहले ही मुनाफ़ा कमा कर दे देती है। वैसे तो किसान इस समय कई फसलों को लगा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी 7 सब्जियों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मार्केट में डिमांड तगड़ी रहती है।

**मिर्च की खेती**- मिर्च ऐसी सब्जियों में आती है, जिसकी पूरे साल डिमांड बनी रहती है। भारतीय खाने में मिर्च शामिल होती ही है। बाजार में ज्यादा हरी दिखने वाली मिर्च की हाई डिमांड रहती है इसलिए इनकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

**करेला**- जनवरी में करेले की खेती भी खूब की जाती है। अच्छे उत्पादन के लिए मचान विधि का उपयोग किया जा सकता है। जितना जल्दी माकेज़्ट में करेला पहुंचेगा उसका उतना ज्यादा दाम मिलेगा।

**प्याज की खेती**- जनवरी महीने में प्याज की रोपाई भी की जाती है। वैसे तो सदिज़्यों में भी हरे प्याज की डिमांड रहती है, लेकिन इसके बाद भी लाल के साथ हरे प्याज डिमांड में बने रहते हैं।

**कंद वाली सब्जियां**- गाजर, शकरकंद, आलू, अदरक, मूली, हल्दी जैसी सब्जियां कंद वाली सब्जियों की श्रेणी में आती है। साल की शुरुआत में इन सब्जियों की भी खेती शुरू की जा सकती है।

**पत्तेदार सब्जियां**- सर्दियों की शुरुआत से ही हरी पत्तेदार सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है। धनिया, मेथी, बथुआ, सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियों की खेती से भी अच्छा मुनाफा हासिल किया जा सकता है।

**टमाटर की खेती**- टमाटर भी ऐसी सब्जियों में शामिल है, जिसकी डिमांड पूरे साल भर रहती है। इसलिए आप इसकी खेती करके भी तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में इसकी खेती करके ज्यादा उत्पादन हासिल किया जा सकता है।

हर साल भारत में लगभग 98 लाख टन सोयाबीन का होता है उत्पादन

# सोयाबीन उत्पादन में भारत दुनिया में पांचवें नंबर पर

## यूनिट लगाने के लिए लाइसेंस जरूरी

# प्रोसेसिंग युनिट लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं सोयाबीन के किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

सरकार लगातार किसानों की आय दुगनी करने के प्रयास में लगी है। किसानों को लाभ हो सके इसके लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही हैं। ऐसे में सोयाबीन उत्पादकों के लिए बड़े फायदे की जानकारी है कि जो किसान सोयाबीन की खेती करते हैं यदि वे प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें तो उनका फायदा दोगुना हो सकता है। इसके लिए सरकार सहायता भी देती है। यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसी जगह का चुनाव कर सकते हैं जहां सोयाबीन की खेती होती हो। इससे कम दाम में सोयाबीन उपलब्ध हो जाएगी।

**कई गुना होगा फायदा:** सोयाबीन को किसानों का सोना कहा जाता है। जिसका कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण बाजार में इसकी डिमांड भी हमेशा हाई रहती है। जो किसान इस गोल्डन सीड की खेती करते हैं उन्हें जबरदस्त मुनाफा होता है। वहीं प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है। यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसी जगह का चुनाव कर सकते हैं जहां सोयाबीन की खेती होती हो। इससे कम दाम में सोयाबीन उपलब्ध हो जाएगी।

सोयाबीन उत्पादन में भारत दुनिया में पांचवें नंबर पर है। हर साल भारत में लगभग 98 लाख टन सोया उत्पादन होता है। जिसमें से सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। इसके अलावा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु है।

**बना सकते हैं कई उत्पाद**- सोयाबीन से तेल के अलावा, सोया बड़ी, टोफू आटा, दूध, बिस्कुट और लेसिथिन जैसे कई उत्पाद बनाए जाते हैं। इतने सारे उत्पादों के कारण सोयाबीन प्रोसेसिंग का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है।

**सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए लाइसेंस की होगी जरूरी**- यदि आप भी यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। इसके अलावा अपने व्यवसाय का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है।

### सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट में कैसे होता है काम

सोयाबीन प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन से मिट्टी और कचरा अलग करने के लिए उसे छाना जाता है। इसके बाद भी यदि सोयाबीन साफ़नहीं होती तो मशीन में उन्हें डालकर डंठल, कंकड़ और छिलका हटाकर साफ़ किया जाता है। अच्छे से साफ़करने के बाद सोयाबीन की दाल का निर्माण किया जाता है। इसके बाद दालों से छिलके को अलग करने की प्रोसेस की जाती है। दाल से जब छिलके हट जाते हैं तो उन्हें ट्रैकर में डालकर दालों के छोटे-छोटे टुकड़े किये जाते हैं। फ़िर उन्हें कुकर में डालकर उबाला जाता है। जब यह अच्छे से मुलायम हो जाते हैं तब फ्लेक्स मशीन के जरिये केक तैयार किया जाता है। अब इस केक से तेल निकाला जाता है। जब तेल निकल जाता है तो तेल को रिफाइन करके उसे बेचने के लिए पैक कर लिया जाता है। इसके बाद निकली खली से डीऑयल केक बनाया जाता है। इसकी ग्रेडिंग की जाती है। इसी खली से सोयाबड़ी और टोस्ट बनाई जाती है। इसके अलावा पशुओं के चारे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

40 से 45 फीसदी से लेकर हो सकती है शत प्रतिशत हानि

# पछेती झुलसा रोग: आलू की फसल को बर्बाद कर सकता है , कैसे करें बचाव

भोपाल। जागत गांव हमार

आलू की फसल में नाशीजीवों (खरपतवारों, कीटों व रोगों) से लगभग 40 से 45 फीसदी की हानि होती है। कभी कभी यह हानि शत प्रतिशत होती हैं। आलू की सफल खेती के लिए आवश्यक है की समय से पछेती झुलसा रोग का प्रबंधन किया जाए। यह रोग फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के कारण फैलता है। आलू का पछेती अंगमारी रोग बेहद विनाशकारी है। आयरलैंड का भयंकर अकाल जो साल 1945 में पड़ा था, इसी रोग के द्वारा आलू की पूरी फसल तबाह हो जाने का ही नतीजा था। जब वातावरण में नमी व रोशनी कम होती है और कई दिनों तक बरसात या बरसात जैसा माहौल होता है, तब इस रोग का प्रकोप पौधे पर पत्तियों से शुरू होता है।

**दिखाई देने वाले लक्षण**- यह रोग 4 से 5 दिनों के अंदर पौधों की सभी हरी पत्तियों को नष्ट कर सकता है। पत्तियों की निचली सतहों पर सफेद रंग के गोले गोले बन जाते हैं, जो बाद में भूरे व काले हो जाते हैं। पत्तियों के

बीमार होने से आलू के कंदों का आकार छोटा हो जाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इस के लिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान मुनासिब होता है। आद्रज्ञता इसे बढ़ाने में मदद करती है। पछेती झुलसा के विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक तापमान और नमी हैं।

स्पोरैंगिया निचली पत्ती की सतहों और संक्रमित तनों पर बनते हैं जब सापेक्षिक आर्द्रता 90प्रतिशत होती है। बीजाणु बनाने की प्रक्रिया (स्पोरुलेशन) 3-26 डिग्री सेल्सियस (37-79 डिग्री फारेनहाइट) से हो सकता है, लेकिन इष्टतम सीमा 18-22 डिग्री सेल्सियस (64-72 डिग्री फारेनहाइट) है। आलू एवं की सफल खेती के लिए आवश्यक है की इस रोग के बारे में जाने एवं प्रबंधन हेतु आवश्यक फफूंदनाशक पहले से खरीद कर रख ले एवं ससमय उपयोग करें अन्यथा रोग लगने के बाद यह रोग आप को इतना समय नहीं देगा की आप तैयारी करें। पूरी फसल नष्ट होने के लिए 4 से 5 दिन पर्याप्त है।

### पछेती झुलसा रोग का प्रबंधन

जब तक आलू के खेत में इस रोग के लक्षण नही दिखाई देता है, तब तक मैंकोजेब युक्त फफूंदनाशक 0.2 प्रतिशत की दर से यानि दो ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते है, लेकिन एक बार रोग के लक्षण दिखाई देने के बाद मैंकोजेब नामक देने का कोई असर नहीं होगा इसलिए जिन खेतों में बीमारी के लक्षण दिखने लगे हों उनमें साइमोइक्सेनील मैनकोजेब दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसी प्रकार फेनोमेडोन मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। मेटालैक्सिल एवं मैनकोजेब मिश्रित दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर भी छिड़काव किया जा सकता है। एक हेक्टेयर में 800 से लेकर 1000 लीटर दवा के घोल की आवश्यकता होगी। छिड़काव करते समय पैकेट पर लिखे सभी निर्देशों का अक्षरश: पालन करें।

# काली मिर्च की खेती किसानों को कर सकती है मालामाल

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत में जितनी काली मिर्च की खेती होती है उसमें से अकेले केरल में ही 98 प्रतिशत उत्पादन होता है। केरल के बाद कर्नाटक और फिर तमिलनाडु में काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है।

भारतीय मसाले विदेशों में भी काफी फेमस है। मसालों में कई चीजें शामिल हैं, जिनमें से एक काली मिर्च भी है। जिसे मसालों का राजा कहते हैं। इसके लाभकारी गुणों के कारण इस फसल की मार्केट में खूब डिमांड रहती है। किसान इस फसल की खेती से जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं।

**इस राज्य में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन**- भारत में जितनी काली मिर्च की खेती होती है उसमें से अकेले केरल में ही 98 प्रतिशत उत्पादन होता है। केरल के बाद कनाज्टक और फ़िर तमिलनाडु में काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के कोंकण में भी काली मिचज की दुर्लभ किस्म की खेती की जाती है।

**काली मिर्च की खेती के लिए इन बातों का रखें ख्याल**- काली मिर्च की फसल के अच्छे उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडे इलाके की आवश्यकता नहीं होती। हवा में नमी रहना जरूरी है। इससे बेल का विकास तेजी से होता है। इस फसल के लिए मध्यम से भारी मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। ऐसी जलवायु जो सुपारी और नारियल की फसल के लिए बेहतर मानी जाती है उसमें काली मिर्च की खेती अच्छे से होती है। अपने क्षेत्र के वातावरण के अनुसार किस्मों का चयन करें। इस फसल को छाया में उगाना चाहिए।

**काली मिर्च को आम के पेड़ों पर भी लगाया जा सकता है**- नारियल सुपारी के पेड़ों पर भी काली मिचज की

बेल लगाई जाती है। यदि आप केवल काली मिर्च ही लगा रहे हैं तो बेलों को सहारा देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप चाहे तो लकड़ी का सहारा ले सकते हैं। बेलों को चार से पांच मीटर ही लंबी होने दें। इससे ज्यादा होने पर आधार से इसकी कटाई कर दें।

**ये हैं काली मिर्च की उन्नत किस्में:** यदि आप भी काली मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इसलिए बेहतर किस्मों का चयन करें। इन किस्मों में श्रीकारा, पंचमी, पेयुर मिरी अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित पेयुर-1 और पेयुर-4, पूर्णिमा।

### गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान (एईआरसी) में प्लेटिनम जुबली सम्मेलन

# भारत को विश्व की फूड बास्केट बनाने में जुटी है सरकारः केंद्रीय कृषि मंत्री

**भोपाल। जागत गांव हमार**

भारत की कृषि क्षेत्र अन्य देशों से मजबूत है। इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार सदा प्रयासरत है। कृषि क्षेत्र के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को जताते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को विश्व की फूड बास्केट बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने यह बात पूणे स्थित गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान (एईआरसी) के प्लेटिनम जुबली सम्मेलन के दौरान कही। चौहान ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।

कृषि क्षेत्र में शोध का विस्तार जरूरी

चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि किसानों तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिक और किसान मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में कई योजनाओं पर काम कर रही है ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक और नए समाधान उपलब्ध कराए जा सकें।

**प्राकृतिक खेती और भंडारण क्षमता पर जोर**– कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती को समय की मांग बताया और कीटनाशकों के अनियंत्रित प्रयोग को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल पयाज्वरण के लिए लाभकारी है बल्कि उत्पादन में भी वेल्यू एडिशन करती है। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।

**किसानों के उत्पादों के लिए नई योजना**– चौहान ने कहा कि किसानों के उत्पादों को दूर-दराज के बाजारों तक पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर नई योजना पर काम कर रही हैं। इससे किसानों को अपने उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

## भाषा की बाधा को दूर करने की पहल

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां केवल अंग्रेजी तक सीमित न रहें, बल्कि भारत की विभिन्न भाषाओं में भी प्रकाशित हों। इससे लैब टू लैंड की दूरी को कम करने में मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफइंडिया लिमिटेडने अपने 22वें स्थापना दिवस पर 'फल सुरक्षा बीमा' लॉन्च किया, जो केले और पपीते की फसलों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

## नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर 2024 को नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ करेंगे। चौहान ने बताया कि इस परियोजना से देश के बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिलेगी। इस परियोजना का उद्देश्य अधिक पानी वाले क्षेत्रों से कम पानी वाले क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना है।

## किसानों के लिए अन्य पहल

कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बताया कि सरकार ने पिछले साल 1 ı94 मीट्रिक टन सब्सिडी किसानों को प्रदान की है। साथ ही, किसानों को महाजन के पास जाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए किसान क्रेडिट काडज़् की सुविधा दी गई है। 2014 से 2024 के बीच सरकार ने कई फ्सलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर किसानों को राहत प्रदान की है।

### आईसीएआर-केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ने लांच किया

# एवी मेल मोबाइल एआई लैब, भेड़ प्रजनन बढ़ाने में मिलेगी मदद

**नई दिल्ली। जागत गांव हमार**




आईसीएआर-केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर ने भेड़ों के प्रजनन को बढ़ाने के लिए 'एवी मेल'/‚1द्व ङ्कङ्करु नामक मोबाइल कृत्रिम गभाधज़्न (एआई) प्रयोगशाला लॉन्च की है। यह सुविधा किसानों को उनके गांव में ही उन्नत प्रजनन सेवाएं प्रदान करती है। यह एवी मेल अत्याधुनिक सुविधा भेड़ उद्योग में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करते हुए सीधे किसानों के दरवाजे तक एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन और कृत्रिम गर्भाधान एआई सेवाएं प्रदान करके प्रजनन प्रथाओं को बदलने के लिए डिज़ाइन की गई है।

**परिणाम और प्रभाव**– एवी मेल का व्यावहारिक प्रभाव राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों में पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है, जहाँ इसे पाँच गाँवों में लागू किया गया था। 10 किसानों की 450 भेड़ों पर कृत्रिम गभाधज़्न सफ्लतापूवज़्क किया गया, जिससे 58त्न की प्रभावशाली भेड़-बकरियाँ पैदा होने की दर हासिल हुई। ये परिणाम भेड़ों की उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार करके छोटे किसानों के उत्थान के लिए एवी मेल की क्षमता को रेखांकित करते हैं।

इस पहल को केंद्रीय मंत्रियों और विशेषज्ञों द्वारा सराहा गया है। 'एवी मेल' का डिज़ाइन लागत-प्रभावी और खेत-तैयार है, जिससे यह किसानों, अनुसंधान संस्थानों और पशुपालन विभागों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है।

## 'एवी मेल' की प्रमुख विशेषताएं

- भेड़ों में एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन और एआई सेवाएं प्रदान करती है।
- वीर्य संग्रह, मूल्यांकन और प्रसंस्करण के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करती है।
- अन्य पशुओं जैसे बकरी, सुअर, और घोड़ों के लिए भी उपयोगी है।
- किसानों के लिए जागरूकता और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन।

## भविष्य की संभावनाएं

एवी मेल उन्नत जर्मप्लाज्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारत के भेड़ उद्योग को नया आयाम देने का वादा करता है। यह पहल अत्याधुनिक प्रजनन पद्धतियों को सीधे किसानों तक पहुंचाकर, एवी मेल पशुधन उत्पादकता नवाचार में आईसीएआर-सीएसडब्ल्यूआरआई के नेतृत्व को मजबूत करती है और पशुधन क्षेत्र में टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

## पास्ता निर्माण यूनिट की स्थापना से परिवार में आई खुशी

**हरदा।** उद्यानिकी विभाग की 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना' के तहत हरदा जिले के टिमरनी निवासी अर्जुन सिंह राजपूत ने पास्ता निमाज़्ण यूनिट स्थापित की। जिससे नियमित आय होने से परिवार खुश है। राजपूत ने बताया कि इसके लिये उसे 1.98 लाख रुपये की मदद उद्यानिकी विभाग से मिली है। उन्होंने बताया कि वह मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 50 क्विंटल पास्ता तैयार कर लेता है और इसे बाजार में बिक्री करता है। अर्जुन ने बताया कि उसने अपने सहयोग के लिये 2 कर्मचारी भी पास्ता निर्माण यूनिट में लगा रखे हैं। इस व्यवसाय से अर्जुन को हर माह 40 से 50 हजार रुपये की शुद्ध आय नियमित रूप से होने लगी है।

## जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दड्डद्बह्लiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304
4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncgupt-abau@gmail.com, मोबा- 8789708210
5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184
6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः अरविंद मिश्रा, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)